



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 28 फरवरी, 2006/9 फाल्गुन, 1927

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 फरवरी, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-अनु०बजट/1-15/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 28 फरवरी, 2006 को हिमाचल

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ  
हेतु प्रेषित किया जाता है ।

(जे० आर० ग.  
सचिव,

हि० प्र० विधान सभा ।

## हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2006 है ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 14,31,39,11,806 रुपए (चौदह सौ इक्कतीस करोड़, उनतालीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ छः रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2005-2006 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।
3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए 14,31,39,11,806 रुपये की राशि जारी करना ।

विनियोग ।

## अनुसूची

2006.

(धारा 2 और 3 देखें)

सांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत रुपये	संचित निधि पर प्रभारित रुपये	जोड़ रुपये
1	2	3	4	5
1	विधान सभा (राजस्व) (पूंजी)	40,25,000 55,00,000	3,00,000 —	43,25,000 55,00,000
2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् (राजस्व) (पूंजी)	58,05,000 —	19,07,000 —	77,12,000 —
3	न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	13,22,00,000 —	1,39,49,500 —	14,61,49,500 —
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	6,02,90,000 —	47,92,000 —	6,50,82,000 —
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व) (पूंजी)	11,68,77,000 1,19,99,000	35,67,788 —	12,04,44,788 1,19,99,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व) (पूंजी)	5,40,68,000 —	— —	5,40,68,000 —
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व) (पूंजी)	17,83,62,011 3,02,00,000	— —	17,83,62,011 3,02,00,000
8	शिक्षा (राजस्व) (पूंजी)	1,11,53,09,000 1,21,70,000	— —	1,11,53,09,000 1,21,70,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व) (पूंजी)	16,44,17,000 3,67,98,000	— —	16,44,17,000 3,67,98,000
10	लोक निर्माण - भवन (राजस्व) (पूंजी)	38,37,17,000 3,16,45,000	— —	38,37,17,000 3,16,45,000

असाधारण		2	3	4	5
De- mand No.			रुपये	रुपये	रुपये
	(राजस्व)	11,14,58,200	—	11,14,58,200	
	(पूँजी)	5,30,00,000	—	5,30,00,000	
	(राजस्व)	24,44,05,000	—	24,44,05,000	
	(पूँजी)	—	—	—	
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व) 1,98,72,05,000 (पूँजी) 93,05,92,000	— 5,40,02,000	1,98,72,05,000 98,45,94,000	
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व) 12,79,72,125 (पूँजी) —	— —	12,79,72,125 —	
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व) 10,87,39,000 (पूँजी) 1,92,98,000	— —	10,87,39,000 1,92,98,000	
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व) 28,83,82,400 (पूँजी) 3,54,64,500	— —	28,83,82,400 3,54,64,500	
17	सड़कें और पुल	(राजस्व) 34,88,89,000 (पूँजी) 62,41,47,000	— 50,82,000	34,88,89,000 62,92,29,000	
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व) 14,80,05,102 (पूँजी) 2,40,00,000	2,77,373 —	14,82,82,475 2,40,00,000	
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) 11,71,74,480 (पूँजी) 25,01,27,660	— —	11,71,74,480 25,01,27,660	
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) 12,72,85,000 (पूँजी) —	4,57,000 —	12,77,42,000 —	
21	सहकारिता	(राजस्व) 52,13,000 (पूँजी) 2,02,00,000	— —	52,13,000 2,02,00,000	
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व) 91,33,000 (पूँजी) 1,49,000	— —	91,33,000 1,49,000	

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	Rs.
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व) (पूँजी)	50,91,40,000 —	10,000 —	1,98,72,05,000 98,45,94,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व) (पूँजी)	3,20,77,000 —	— —	3,20,72,125 —
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व) (पूँजी)	23,25,33,720 1,63,42,935	— —	23,25,33,720 1,63,42,935
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) (पूँजी)	26,35,000 —	— 5,35,55,000	26,35,000 5,35,55,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) (पूँजी)	3,77,68,000 —	— —	3,77,68,000 —
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास (राजस्व) (पूँजी)	2,76,51,000 —	— —	2,76,51,000 —
29	वित्त (राजस्व) (पूँजी)	3,16,79,000 —	40,00,16,012 4,76,10,50,000	43,16,95,012 4,76,10,50,000
30	विविध सामान्य सेवायें (राजस्व) (पूँजी)	5,03,52,000 25,00,000	— —	5,03,52,000 25,00,000
31	जन जातीय विकास (राजस्व) (पूँजी)	18,000 14,80,28,000	— —	18,000 14,80,28,000
	जोड़ (राजस्व)	6,76,27,85,038	42,52,76,673	7,18,80,61,711
	(पूँजी)	2,25,21,61,095	4,87,36,89,000	7,12,58,50,095
	कुल जोड़	9,01,49,46,133	5,29,89,65,673	14,31,39,11,806

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

- |    |   |
|----|---|
| 1  |   |
| 27 | Labour, Empi, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के and Traini प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार                                    |
| 28 | Urbanयों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को Tow लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध pl. लिए पुरःस्थापित है। |

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :  
तारीख 28 फरवरी, 2006.

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें**

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन ए.-सी. (2) 1/2005]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 1 of

# THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2006.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2006.

Issue of a further sum of Rs. 14,31,39,11,806 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 14,31,39,11,806 (Fourteen hundred thirty one crore, thirty nine lakh and eleven thousand and eight hundred six rupees only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.



THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

De- mand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on the Consolidated Fund Rs.	Rs.
1	2		3	4	5
1	Vidhan Sabha	(Revenue) (Capital)	40,25,000 55,00,000	3,00,000 —	43,25,000 55,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue) (Capital)	58,05,000 —	19,07,000 —	77,12,000 —
3	Administration of Justice	(Revenue) (Capital)	13,22,00,000 —	1,39,49,500 —	14,61,49,500 —
4	General Administration	(Revenue) (Capital)	6,02,90,000 —	47,92,000 —	6,50,82,000 —
5	Land Revenue and District Administration.	(Revenue) (Capital)	11,68,77,000 1,19,99,000	35,67,788 —	12,04,44,788 1,19,99,000
6	Excise and Taxation	(Revenue) (Capital)	5,40,68,000 —	— —	5,40,68,000 —
7	Police and Allied Organisations	(Revenue) (Capital)	17,83,62,011 3,02,00,000	— —	17,83,62,011 3,02,00,000
8	Education	(Revenue) (Capital)	1,11,53,09,000 1,21,70,000	— —	1,11,53,09,000 1,21,70,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue) (Capital)	16,44,17,000 3,67,98,000	— —	16,44,17,000 3,67,98,000
10	Public Works—Building	(Revenue) (Capital)	38,37,17,000 3,16,45,000	— —	38,37,17,000 3,16,45,000
11	Agriculture	(Revenue) (Capital)	11,14,58,200 5,30,00,000	— —	11,14,58,200 5,30,00,000
12	Horticulture	(Revenue) (Capital)	24,44,05,000 —	— —	24,44,05,000 —

1	2	3	4	
		Rs.	Rs.	
13	Irrigation and Flood Control, Water Supply and Sanitation	(Revenue) 1,98,72,05,000 (Capital) 93,05,92,000	— 5,40,02,000	
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries.	(Revenue) 12,79,72,125 (Capital) —	— —	12,79,72,125
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue) 10,87,39,000 (Capital) 1,92,98,000	— —	10,87,39,000 1,92,98,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue) 28,83,82,400 (Capital) 3,54,64,500	— —	28,83,82,400 3,54,64,500
17	Roads and Bridges	(Revenue) 34,88,89,000 (Capital) 62,41,47,000	— 50,82,000	34,88,89,000 62,92,29,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue) 14,80,05,102 (Capital) 2,40,00,000	2,77,373 —	14,82,82,475 2,40,00,000
19	Social Justice and Empowerment.	(Revenue) 11,71,74,480 (Capital) 25,01,27,660	— —	11,71,74,480 25,01,27,660
20	Rural Development	(Revenue) 12,72,85,000 (Capital) —	4,57,000 —	12,77,42,000 —
21	Co-operation	(Revenue) 52,13,000 (Capital) 2,02,00,000	— —	52,13,000 2,02,00,000
22	Food and Warehousing	(Revenue) 91,33,000 (Capital) 1,49,000	— —	91,33,000 1,49,000
23	Water and Power Development	(Revenue) 50,91,40,000 (Capital) —	10,000 —	50,91,50,000 —
24	Printing and Stationery	(Revenue) 3,20,77,000 (Capital) —	— —	3,20,77,000 —
25	Road and Water Transport	(Revenue) 23,25,33,720 (Capital) 1,63,42,935	— —	23,25,33,720 1,63,42,935
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue) 26,35,000 (Capital) —	— 5,35,55,000	26,35,000 5,35,55,000

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SM-2

			3	4	5
			Rs.	Rs.	Rs.
	Employment	(Revenue)	3,77,68,000	—	3,77,68,000
	ing	(Capital)	—	—	—
	Development,	(Revenue)	2,76,51,000	—	2,76,51,000
	n and Country	(Capital)	—	—	—
	Planning and Housing				
29	Finance	(Revenue)	3,16,79,000	40,00,16,012	43,16,95,012
		(Capital)	—	4,76,10,50,000	4,76,10,50,000
30	Miscellaneous General	(Revenue)	5,03,52,000	—	5,03,52,000
	Services	(Capital)	25,00,000	—	25,00,000
31	Tribal Development	(Revenue)	18,000	—	18,000
		(Capital)	14,80,28,000	—	14,80,28,000
Total			(Revenue)	42,52,76,673	7,18,80,61,711
			(Capital)	4,87,36,89,000	7,12,58,50,095
Grand Total			9,01,49,46,133	5,29,89,65,673	14,31,39,11,806

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 203 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2005-2006.

**VIRBHADRA SINGH,**  
*Chief Minister.*

SHIMLA :

The 28th February, 2006.

---

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF  
THE CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department File No. Fin. A-C (2) 1/2005]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2006 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 28 फरवरी, 2006 / 9 फाल्गुन, 1927

---

कार्यालय उपायुक्त जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचनाएं

नाहन, 2 जनवरी, 2006

संख्या पीसीएन-एसमएआर(निर्वाचन)/2005-01-251.-हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर० एस० नेगी (भा० प्र० से०), उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हि० प्र०, जिला सिरमौर में दिसम्बर, 2005 में हुए सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप